बकाया को इक्विटी में बदलने से वीआई को मिलेगी मदद

बकाया भुगतान व पूंजीगत खर्च बरकरार रखने के लिए होगी बड़ी रकम की दरकार

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 5 फरवरी

भले ही वोडाफोन आइडिया (वीआई) से बकाया ब्याज भुगतान के बदले इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने के सरकार के निर्णय से इस दबावग्रस्त दूरसंचार कंपनी की समस्याएं काफी हद तक दूर होती नजर आ रही हैं, लेकिन अल्पावधि बकाया भुगतान और भविष्य में पूंजीगत खर्च बरकरार रखने के लिए प्रवर्तकों/निवेशकों से बड़े पूंजी निवेश की जरूरत होगी।

सरकार ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया से स्पेक्ट्रम नीलामी की विलंबित किस्तों से संबंधित ब्याज 16,133 करोड़ रुपये के बकाया ब्याज के बदले कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी मिलने से सरकार 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी भागीदार बन जाएगी।

एक घरेलू ब्रोकरेज फर्म के विश्लेषक का मानना है कि कंपनी में इक्विटी भागीदार के तौर पर सरकार की उपस्थिति (भले ही वह परिचालन जिम्मेदारियों से दूर रहेगी), इस बाजार में निजी क्षेत्र की मौजूदा तीन कंपनियों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता और अल्पावधि कोष उगाही की उम्मीद वोडाफोन आइडिया के परिचालन को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी सफलता है।

विश्लेषकों का मानना है कि हालांकि यह एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन कंपनी की राह में पैदा हुईं विभिन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है, चाहे बात कर्ज की हो या नेटवर्क में निवेश के अभाव की।

एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म के शोध प्रमुख का कहना है, 'प्रतिस्पर्धियों की तरह बड़ा निवेश करने के लिए वोडाफोन आइडिया को कम से कम 3-4 अरब डॉलर की जरूरत होगी। प्रवर्तकों से 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश अनुमान पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगले चार वर्षों के दौरान सरकार को बड़ा भुगतान किया जाना है।'

कंपनी का कुल ऋण 30 सितंबर 2022 तक 2.2 लाख करोड़ रुपये था। इसमें 1.36 लाख करोड़ रुपये की आस्थगित भुगतान संबंधित देनदारियां (हाल में हुई नीलामी में खरीदे स्पेक्ट्रम से संबंधित 17,260 करोड़ रुपये समेत) और 68,590 करोड़ रुपये की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) देयता शामिल हैं, जिनका भुगतान कंपनी द्वारा सरकार को किया जाना है।

वित्तीय लेखाजोखा (करोड़ रुपये)

	राजस्व	एबिटा	शुद्ध लाभ
वित्त वर्ष 23 ई	42,583	17,868	-27,076
सालाना बदलाव (फीसदी)	10.56	11.33	नुकसान
वित्त वर्ष 24 ई	46,698	20,805	-24,419
सालाना बदलाव (फीसदी)	9.66	16.44	नुकसान
वित्त वर्ष 25 ई	50,684	23,515	-21,533
सालाना बदलाव (फीसदी)	8.54	13.02	नुकसान

ई : अनुमान। स्रोत : ब्लूमबर्ग
संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

बदलाव की तैयारी

- **विश्लेषकों का कहना है कि मध्यावधि के दौरान परिचालन बरकरार रखने के लिए कंपनी में पूंजी डालना जरूरी है**
- **इक्विटी हिस्सेदारी मिलने से सरकार 33 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वोडा आइडिया में सबसे बड़ी भागीदार बन जाएगी**
- **विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने कहा, 'प्रतिस्पर्धियों की तरह निवेश करने के लिए कंपनी को 3-4 अरब डॉलर की जरूरत होगी**

वहीं बैंकों और वित्तीय संस्थानों का बकाया 30 सितंबर, 2022 को 15,080 करोड़ रुपये पर था।

वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर्स का पैसा लौटाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इंडस टावर्स वीआई से बकाया प्राप्तियों के संदर्भ में 5,300 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है और यदि अन्य कोष उगाही नहीं हुई तो यह आंकड़ा बढ़ने का अनुमान है।

कंपनी आंतरिक स्रोतों के जरिये और विक्रेताओं के भुगतान में विलंब कर अपना कर्ज भुगतान पूरा करने में सक्षम रही है, लेकिन केयर रेटिंग्स का मानना है कि दीर्घावधि वित्त पोषण इक्विटी निवेश या कर्ज के तौर पर जरूरी है, जिस पर रेटिंग के संबंध में नजर बनाए रखने की जरूरत होगी।

ब्रोकरेज का मानना है कि 30 अरब डॉलर का कर्ज होने की वजह से कंपनी के लिए नए निवेशक आकर्षित करना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इससे इक्विटी निवेशकों के लिए तब तक कमाई करना कठिन हो गया है जब तक कि परिचालन लाभ तेजी से नहीं बढ़ता। एक विश्लेषक ने कहा कि कंपनी हर साल करीब 8,000 करोड़ रुपये का आईएनडी-एएस116 पूर्व समायोजित परिचालन लाभ कमा रही है, जबकि उसे अपना परिचालन बरकरार रखने, ब्याज देनदारियां चुकाने और निवेश करने के लिए के लिए 25,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की जरूरत है।

परिचालन लाभ का यह स्तर पाने के लिए कंपनी को अपना ग्राहक आधार बढ़ाना होगा, दरों में वृद्धि करनी होगी, जिससे कि उसके प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) में मजबूती आ सके।

नवंबर के आंकड़े से संकेत मिलता है कि वोडाफोन आइडिया को अक्टूबर के मुकाबले 18 लाख ग्राहक गंवाने पड़े और शुद्ध स्तर पर यह आंकड़ा 20 लाख के आसपास रहा। यह लगातार सातवां महीना था जब सक्रिय ग्राहक उसके नेटवर्क से दूर हुए और प्रमुख बाजारों में समस्याओं को देखते हुए बाजार भागीदारी नुकसान बरकरार रहने की आशंका है।

सीएलएसए की दीप्ति चतुर्वेदी और सौरभ मल्होत्रा का मानना है कि वित्त वर्ष 2023 के 9 महीनों का पूंजीगत खर्च 3,260 करोड़ रुपये था, जो भारती एयरटेल के भारतीय खर्च से करीब 80 प्रतिशत कम है। पूंजीगत खर्च में कमी मौजूदा कोष उगाही में विलंब बढ़ सकता है। सीएलएसए के विश्लेषकों का मानना है कि भारती और रिलायंस जियो ने दिसंबर 2023/मार्च 2024 तक अपने 5जी नेटवर्क और पूरे भारत में कवरेज के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया है, जिससे वोडाफोन आइडिया के 2.1 करोड़ पोस्टपेड उपभोक्ताओं (जिनका कुल राजस्व में 25 प्रतिशत से ज्यादा योगदान है) के लिए जोखिम बढ़ेगा, क्योंकि इन ग्राहकों द्वारा देश में 5जी पर जोर दिए जाने की संभावना है।

विदेशी निवेशकों ने जनवरी में 28,852 करोड़ रुपये निकाले

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जनवरी में भारतीय शेयर बाजारों से 28,852 करोड़ रुपये निकाले हैं। यह पिछले सात माह का एफपीआई निकासी का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। चीन का आकर्षण बढ़ने के बीच एफपीआई भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

इससे पहले दिसंबर में एफपीआई ने शेयरों में 11,119 करोड़ रुपये का निवेश किया था। नवंबर में उन्होंने शेयर बाजारों में 36,238 करोड़ रुपये का निवेश किया था। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी शोध (खुदरा) प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि आगे चलकर एफपीआई प्रवाह में उतार-चढ़ाव रहेगा, क्योंकि अन्य बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार का प्रदर्शन कमजोर है। आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने जनवरी में शेयरों से शुद्ध रूप से 28,852 करोड़ रुपये की निकासी की। *भाषा*

समान अवसर के लिए एआईएफ के शुल्क ढांचे पर जोर

खुशबू तिवारी
मुंबई, 5 फरवरी

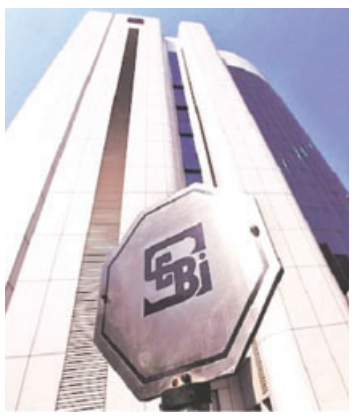

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) उद्योग में गलत जानकारी देकर की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए अपने सदस्यों को प्रशिक्षित किया है। पूंजी बाजार नियामक ने सेवा प्रदाताओं को डायरेक्ट प्लान पेश करने और कमीशन वितरण के लिए ट्रेल मॉडल पर अमल अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है।

बाजार नियामक सेबी अपफ्रंट कमीशन यानी अग्रिम कमीशन को पहले ही खत्म कर चुका है और उसने म्युचुअल फंडों (एमएफ) के लिए डायरेक्ट प्लान पेश किए। पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा उद्योग के लिए भी अपफ्रंट कमीशन पर रोक लगाई गई। उद्योग के कारोबारियों का कहना है कि एआईएफ उद्योग के लिए नया प्रस्ताव समान कारोबार अवसर मुहैया कराएगा और वितरकों के लिए संभावित आर्बिट्राज अवसरों को समाप्त करेगा।

मौजूदा समय में, एआईएफ वितरण के लिए अपफ्रंट कमीशन कुल राशि का 5 प्रतिशत तक है। तुलनात्मक तौर पर, एमएफ वितरकों को चुकाया जाने वाला कमीशन इसका महज एक हिस्सा है।

सेबी ने शुक्रवार को सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए जारी एक चर्चा पत्र में कहा, 'खासकर अन्य योजनाओं के लिए ट्रेल कमीशन के विपरीत इतना ज्यादा अपफ्रंट कमीशन, एआईएफ योजनाओं की भ्रामक जानकारी देकर बिक्री की आशंका बढ़ाता है।' नियामक ने कमीशन के ट्रेल मॉडल को अपनाने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्तावित मानकों के तहत, एआईएफ की सभी श्रेणियों के निवेशकों से परीक्षण के आधार पर वितरण शुल्क वसूला जाएगा। हालांकि कैटेगरी-1 और 2 के एआईएफों को कुछ ज्यादा शुल्क लगाने का अनुमति होगी। यह पहले वर्ष में चुकाए गए अग्रिम शुल्क की मौजूदा वैल्यू के एक-तिहाई पर बना रह सकता है।

नियामक के लिए चिंता का विषय कुल राशि पर अपफ्रंट कमीशन शुल्क है जो वितरकों द्वारा निवेशकों पर लगाया जाता है।

मनीफ्रंट के सह-संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी मोहित गंग का कहना है, 'भले ही निवेश एक बार में नहीं किया गया हो, लेकिन कुल राशि पर पूरा कमीशन मौजूदा समय में अग्रिम तौर पर चुकाया जाता है, क्योंकि वितरक अब इस व्यवस्था को पसंद करते हैं।'

एक ताजा कार्यक्रम में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण गोपालकृष्णन ने कहा, 'इस क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं हैं जिनमें मूल्यांकन और गलत जानकारी देकर की जाने वाली बिक्री की चुनौतियां मुख्य रूप से शामिल हैं, जिससे एआईएफ उद्योग के लिए विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।'

इसके अलावा, सेबी ने निवेशकों, खासकर वित्तीय सलाहकारों के जरिये निवेश करने वालों के लिए कई शुल्क ढांचों की व्यवस्था से दूर होने का प्रस्ताव रखा है।

इन निवेशकों से दोहरे शुल्क वसूले जा रहे थे – परामर्श शुल्क या पोर्टफोलियो प्रबंधन शुल्क के तौर पर, और एआईएफ वितरण शुल्क के रूप में।

डीएसके लीगल में पार्टनर हेमांग पारेख का कहना है, 'यदि निवेशकों को गलत जानकारी देकर बिक्री की जाती है और उनके हितों के साथ समझौता होता है तो सेबी को निवेशक हित सुरक्षित बनाने के लिए ऐसी गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार है।'

सेबी की योजना

- **मौजूदा समय में, एआईएफ वितरण के लिए अपफ्रंट कमीशन कुल राशि का 5 प्रतिशत तक है**
- **सेबी ने खासकर वित्तीय सलाहकारों के जरिये निवेश करने वाले निवेशकों को कई शुल्क ढांचों की व्यवस्था से दूर रखने पर भी ध्यान दिया है**

आईपीओ बाजार : जुलाई 22 के बाद से पहली सुस्त अवधि

बाजार में कंपनियों की सूचीबद्ध प्रक्रिया में रुकावट आ गई है। पिछले महीने, जो जुलाई 2022 के बाद से सुस्त अवधि वाला पहला महीना था, आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों और अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गमों (एफपीओ) से एक भी पैसा नहीं जुटाया गया है।

निवेश बैंकरों का कहना है कि बाजार के उतार-चढ़ाव में तेजी, दुनिया के अन्य बाजारों की तुलना में भारत का कमजोर प्रदर्शन और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निरंतर बिकवाली ने शेयरों की बिक्री को मुश्किल कर दिया।

आम तौर पर कंपनियां आम बजट से पहले शेयरों की बिक्री निपटाने की योजना बनाती हैं। लेकिन अदाणी समूह की प्रमुख फर्म को छोड़कर ज्यादातर कंपनियों ने इससे दूरी बनाई है।

अदाणी एंटरप्राइजेज का 20,000 करोड़ रुपये का एफपीओ, जो 31 जनवरी को बंद हुआ, पूर्ण सदस्यता हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि इसने अपने 'ग्राहकों के हितों' में निर्गम वापस ले लिया।

अमेरिका की शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जारी होने के बाद बाजार में अदाणी समूह के शेयरों में बड़े पैमाने पर गिरावट के बीच यह असाधारण घटनाक्रम सामने आया। इस रिपोर्ट में समूह पर शेयर में हेरफेर और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकरण ने प्राथमिक बाजार का मिजाज बिगाड़ दिया। उन्हें उम्मीद है कि जब तक द्वितीयक बाजार की रफ्तार सकारात्मक नहीं हो जाती है और एफपीआई प्रवाह में सुधार नहीं होता है, तब तक गतिविधि सुस्त रहेगी।

सुंदर सेतुरामन

सुस्ती का माहौल

विशेषज्ञों ने कहा, प्राथमिक बाजार की गतिविधियां कुछ समय और सुस्त बनी रहेंगी

अवधि	पेश आईपीओ	जुटाई रकम (करोड़ रुपये)
जुलाई 22	0	0
अगस्त 22	2	1,402
सितंबर 22	2	1,562
अक्टूबर 22	3	1,309
नवंबर 22	10	10,560
दिसंबर 22	7	4,155
जनवरी 23	1	0

स्रोत : प्राइम डेटाबेस

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT.
THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

EARTH STAHL

EARTHSTAHL & ALLOYS LIMITED

CIN: U27310CT2009PLC021487

Our Company was originally incorporated as "Earthstahl & Alloys Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated December 09, 2009 bearing registration No. 021487 issued by Registrar of Companies, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and CIN No. U27310CT2009PTC021487. Subsequently our Company was converted into a public limited company vide special resolution passed by the shareholders at the Annual General Meeting held on August 27, 2022 and the name of our Company was changed from "Earthstahl & Alloys Private Limited" to "Earthstahl & Alloys Limited" vide fresh Certificate of Incorporation granted to our Company consequent upon conversion into public limited company dated September 21, 2022 by the Registrar of Companies, Chhattisgarh bearing Corporate Identification Number U27310CT2009PLC021487. For further details please refer to chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on page 111 of the Prospectus dated February 02, 2023.

Registered Office: Merlin Jayshree Vihar, Mohani 5 B, Pandri Tarai, Mandi Gate, Raipur, Chhattisgarh- 492001 India.
Contact Person: Rahul Kumar Sinha, Company Secretary & Compliance Officer **Tel No:** +91-8120009626;
E-mail: secretarial@earthstahl.com **Website:** www.earthstahl.com **CIN:** U27310CT2009PLC021487

OUR PROMOTERS: Ravi Thakurdasji Laddha, Rajesh Somani, Prawin Somani and Padam Kumar Jain

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC OFFERING OF 32,40,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH OF EARTHSTAHL & ALLOYS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 40 PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 30 PER EQUITY SHARE) AGGREGATING TO RS. 1296.00 LAKHS ("THE ISSUE"). THE ISSUE INCLUDES A RESERVATION OF 1,68,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 AT A PRICE OF RS. 40 PER EQUITY SHARES AGGREGATING RS. 67.20 LAKHS FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION'). THE ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 30,72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 40 PER EQUITY SHARE, AGGREGATING RS 1228.80 LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE CONSTITUTES 26.47% AND 25.09% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

ISSUE PRICE: RS. 40 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF RS.10 EACH
THE ISSUE PRICE IS 4 TIMES OF THE FACE VALUE

Risks to Investors: i Our company defaulted in servicing its debt obligations during FY 15-16 and FY 16-17 and such debt was settled as at March 31, 2018. Due to delay in commissioning and stabilisation of foundry for manufacturing ductile iron pipe fittings and fall in the steel prices the company had shut down its operations from March 2015 till March 2018. If such circumstances re-occur disrupting the operational and financial margin, the company may close its operations again if not financially feasible.
ii. The Merchant Banker associated with the Issue has handled 21 public issue in the past three years out of which 1 Issues closed below the Issue Price on Listing date
iil. Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoters is
iv. The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2022 for the company at the upper end of the Price Band is 4.83
v. Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2022, 2021 and, 2020 is 51.25%

Sr No	Name of Promoter	Average cost of acquisition per equity share
1	Ravi Thakurdasji Laddha	Rs. 7.79
2	Rajesh Somani	Rs. 10.92
3	Prawin Somani	Rs. 11.24
4	Padam Kumar Jain	Rs. 7.86

BID/ ISSUE PERIOD
BID/ ISSUE OPENED ON: FRIDAY, JANUARY 27, 2023
BID/ ISSUE CLOSED ON: TUESDAY, JANUARY 31, 2023
PROPOSED LISTING: FEBRUARY 08, 2023*

The Issue was made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended **("SCRR")** read with Regulation 253 of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **("SEBI ICDR Regulations")** wherein not more than 30% of the Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** (the **"QIB Portion"**). Further, not less than 35% of the Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Issue was made available for allocation to RIIs in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, subject to valid Bids having been received from them at or above the Issue Price. All potential Bidders were required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount **("ASBA")** process providing details of their respective bank account (including UPI ID for RIBs using UPI Mechanism), in which the corresponding Bid Amounts were blocked by the SCSBs or the Sponsor Bank, as applicable. For details, see ***"Issue Procedure"*** on page 215 of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited. The trading is proposed to be commenced on or about February 08, 2023*.
**Subject to the receipt of listing and trading approval from the BSE SME Platform.*
The Issue received 75,541 Applications for 72,27,03,000 Equity Shares (before technical rejections) resulting in 223.06 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before technical rejections):

Detail of the Applications Received:

Sr. No.	Category	No. of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (in Rs.)
1	Retail-Individual Investors	68,888	20,66,64,000	10,77,000	191.89	8,26,60,11,000
2	Non-Institutional Investors	6,631	48,31,83,000	10,77,000	448.64	19,32,69,84,000
3	Market Maker	1	1,68,000	1,68,000	1.00	67,20,000
4	Qualified Institutional Buyers	21	3,26,88,000	9,18,000	35.61	1,30,75,20,000
	Total	**75,541**	**72,27,03,000**	**32,40,000**	**223.06**	**28,90,72,35,000**

Final Demand: A summary of the final demand as per BSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr.No.	Bid Price	Bids Quantity	% of Total	Cumulative Total	% Cumulative Total
1	38	120	4,89,000	76,08,54,000	0.06
2	39	18	54,000	76,03,65,000	0.01
3	40	39,472	61,58,40,000	76,03,11,000	80.94
4	CUT OFF	48,157	14,44,71,000	14,44,71,000	18.98
	TOTAL	**87,767**	**76,08,54,000**		

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being BSE Limited on February 03, 2023.

1) Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections)
The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 40 per Equity Share, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 188.04 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 10,77,000 Equity Shares to 359 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied	% of Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Shares Allotted
Retail Individual Investors	67,506	100.00	20,25,18,000	100.00	3,000	1:188	10,77,000

2) Allotment to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections)
The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Issue Price of Rs. 40 per Equity Share or above, was finalized in consultation with BSE. The category has been subscribed to the extent of 440.78 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 10,77,000 Equity Shares to 336 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under *(Sample Basis)*:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications Received	% of Total	Total No. of Shares Applied in Each Category	% of Total	No. of Equity Shares Allotted per Applicant	Ratio	Total No. of Shares Allotted
6000	2444	37.48	14664000	3.09	3000	1:222	33000
9000	492	7.55	4428000	0.93	3000	1:164	9000
12000	367	5.63	4404000	0.93	3000	3:367	9000
15000	264	4.05	3960000	0.83	3000	1:88	9000
27000	514	7.88	13878000	2.92	3000	5:257	30000
30000	225	3.45	6750000	1.42	3000	1:45	15000
33000	105	1.61	3465000	0.73	3000	1:35	9000
36000	77	1.18	2772000	0.58	3000	2:77	6000
66000	19	0.29	1254000	0.26	3000	1:19	3000
69000	20	0.31	1380000	0.29	3000	1:20	3000
72000	22	0.34	1584000	0.33	3000	1:22	3000
75000	58	0.89	4350000	0.92	3000	3:58	9000
876000	1	0.02	876000	0.18	3000	1:1	3000
885000	1	0.02	885000	0.19	3000	1:1	3000
906000	1	0.02	906000	0.19	3000	1:1	3000
915000	1	0.02	915000	0.19	3000	1:1	3000
1113000	1	0.02	1113000	0.23	3000	1:1	3000
1125000	2	0.03	2250000	0.47	3000	1:1	6000
1134000	21	0.32	23814000	5.02	3000	6:7	54000
1137000	1	0.02	1137000	0.24	3000	1:1	3000
1191000	1	0.02	1191000	0.25	3000	1:1	3000
1230000	1	0.02	1230000	0.26	3000	1:1	3000
1245000	1	0.02	1245000	0.26	3000	1:1	3000
1248000	1	0.02	1248000	0.26	3000	1:1	3000
1404000	1	0.02	1404000	0.30	3000	1:1	3000
1875000	1	0.02	1875000	0.39	3000	1:1	3000
1950000	1	0.02	1950000	0.41	3000	1:1	3000
1956000	1	0.02	1956000	0.41	3000	1:1	3000
2001000	1	0.02	2001000	0.42	6000	1:1	6000
2499000	1	0.02	2499000	0.53	6000	1:1	6000
2874000	1	0.02	2874000	0.61	6000	1:1	6000
3072000	4	0.06	12288000	2.59	6000	1:1	24000
3000 additional shares allocated for serial no 273 in the ratio of 1:4					3,000	1:4	3000

3) Allotment to QIBs (After Technical Rejections)
Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 40 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with BSE. This category has been subscribed to the extent of 35.61 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 9,18,000 Equity Shares, which were allotted to 21 successful Applicants.

Category	FI's	BANKS	MF's	IC	AIF	FIIs/ FPIs	OTHERS	TOTAL
QIB	87,000	87,000	-	-	-	4,02,000	3,42,000	9,18,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on February 03, 2022 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being BSE Ltd and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before February 03, 2022. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below.
The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on SME Platform of BSE Limited within six working days from the date of the closure of the Issue.
Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated February 02, 2023 filed with the Registrar of Companies, Chhattisgarh ("RoC").

INVESTORS PLEASE NOTE
The details of the allotment made has been hosted on the website of the Registrar to the Issue, Bigshare Services Private Limited at website: www.bigshareonline.com
All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

Bigshare Services Pvt. Ltd.

BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED
Address: S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093, India.
Tel. No.: +91 22 6263 8200; **Website:** www.bigshareonline.com; **Email:** ipo@bigshareonline.com
CIN: U99999MH1994PTC076534; **Contact Person:** Mr. Babu Rapheal; **SEBI Regn. No.:** MB/INR000001385

On behalf of Board of Directors
Earthstahl & Alloys Limited
Sd/-
Rahul Kumar Sinha
Company Secretary & Compliance Officer
M.No. A66805

Place: Raipur
Date: February 04, 2023

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF EARTHSTAHL & ALLOYS LIMITED.

Disclaimer: Earthstahl & Alloys Limited has filed the Prospectus with the RoC on **February 02, 2023** and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The Prospectus is available on the website of SME Platform of BSE at www.bsesme.com and on the websites of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see **"Risk Factors"** beginning on page 24 of the Prospectus.
The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended **(the "Securities Act")** or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being offered and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such offers and sales are made. There will be no public offering in the United States.

MAHESHWARI